भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1727**

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण का आकलन**

**1727. श्री कंवर सिंह तंवरः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में फसल विविधीकरण और मूल्यवर्धन की संभावनाओं का आकलन किया है, और अमरोहा, हसनपुर, जोया और धनाउरा जैसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में बागवानी, सब्जी उत्पादन और कृषि संबंधी कार्यकलापों को अधिक लाभदायक विकल्पों के रूप में प्रोत्साहित किए जाने संबंधी आकलन क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और आजीविका में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के कार्यक्रमों, प्रदर्शनी संकुलों, किसान प्रशिक्षण मॉड्यूल और संस्थागत सहायता प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) पानी की अधिक खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने के उद्देश्य से मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 से प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) नामक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। सीडीपी-धान उत्तर प्रदेश के 11 जिलों जैसे अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और मैनपुरी में कार्यान्वित है। सीडीपी योजना को वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की फसल को प्रतिस्थापित करने के लिए विस्तारित किया गया।

राज्य सरकारों के माध्यम से भारत सरकार किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के तहत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बागवानी फसलों जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये योजनाएं पूरे देश में लागू हैं और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए लचीलापन भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी हस्तक्षेप और अभिसरण नीतियों के माध्यम से फसल विविधीकरण पर ध्यान देती है।

इसके अतिरिक्त, डीएएंडएफडब्ल्यू ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएफएसआर), मोदीपुरम के माध्यम से एनएफएसएनएम के तहत 1326.60 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए "फसल विविधीकरण" पर एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं ताकि राज्य सरकारों के विस्तार पदाधिकारियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नई तकनीकों के अनुकूलन को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2024-25 के दौरान अमरोहा जिले के केवीके ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 1850 किसानों को तकनीकों और पद्धतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, किसानों की आजीविका में सहायता देने के लिए केवीके ने 177 किसानों को एकीकृत खेती प्रणाली (आईएफएस) माध्यम में विभिन्न उद्यमों पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा योजना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले सहित देश के 724 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के उन प्रयासों का समर्थन करना है जिसके तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु- प्रतिरोधक कृषि पद्धतियां और प्राकृतिक खेती आदि सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नई तकनीकों और बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में बड़ी संख्या में किसानों (छोटे और सीमांत किसानों सहित) को जागरूक बनाना है। यह जागरूकता किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करने और कृषि विद्यालयों का आयोजन आदि जैसे विभिन्न विस्तार क्रियाकलापों के माध्यम से फैलाई जा रही है।

******